भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2664

दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

नक्शा कार्यक्रम का विस्तार

2664. श्री बसवराज बोम्मईः

क्या ***ग्रामीण विकास*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) क्षमता कार्यक्रम भूमि संबंधी धोखाधड़ी और विवादों की संभावना को कम करने में सहायक होगा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नक्शा कार्यक्रम का पूरे देश में, राज्यवार, विशेषकर कर्नाटक राज्य में, कब तक विस्तार किया जाएगा?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) जी हाँ । भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा नक्शा कार्यक्रम, भू-स्थानिक रूप से सक्षम, स्पष्ट और कानूनी रूप से प्रामाणिक शहरी भूमि अभिलेखों के सृजन के लिए डिजाइन किया गया है । इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक, कानूनी स्पष्टता और पारदर्शी संपत्ति अभिलेख प्रदान करके भूमि संबंधी धोखाधड़ी और विवादों को कम करना है। इस कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक रूप से मान्य और स्थानिक रूप से संदर्भित ऐसे संपत्ति अभिलेखों के सृजन का प्रावधान है जो स्वामित्व के कानूनी साक्ष्य के रूप में काम कर सकें। इससे कानूनी स्पष्टता को बढ़ावा मिलता है और भूमि स्वामित्व में अस्पष्टता कम हो जाती है जिससे धोखाधड़ी या विवादित लेनदेन की संभावना भी कम हो जाती है। ये अभिलेख एक समर्पित वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म के साथ-साथ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी पोर्टलों पर आसानी से सार्वजनिक पहुंच के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।

नक्शा के अंतर्गत क्षमता निर्माण घटक एक मुख्य स्तंभ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के अधिकारियों, क्षेत्र सर्वेक्षण टीमों और तकनीकी एजेंसियों सहित सभी हितधारकों को हवाई (एरियल) डेटा अधिग्रहण, जमीनी सर्वेक्षण, डेटा सत्यापन और विवाद समाधान की मानक प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाए। इससे सर्वेक्षण और डेटा प्रबंधन प्रक्रियाओं में स्थिरता, सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

(ग) नक्शा कार्यक्रम का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। इसकी कार्यप्रणाली का परीक्षण करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करने के लिए वर्तमान में देश भर के 157 शहरी स्थानीय निकायों में इस कार्यक्रम का पायलट परीक्षण चरण चल रहा है।

कर्नाटक राज्य में, नक्शा कार्यक्रम के चल रहे पायलट चरण के अंतर्गत 10 शहरी स्थानीय निकायों का चयन किया गया है। ये यूएलबी निम्नानुसार हैं:

1. बागलकोट नगर निगम - बागलकोट
2. भाग्यनगर नगर पंचायत - कोप्पल
3. सिरगुप्पा नगर निगम - बेल्लारी
4. बोरगाव नगर पंचायत - बेलगावी
5. गोकक नगर निगम - बेलगावी
6. बसवकल्याण नगर निगम - बीदर
7. चिक्कमंगलुरु नगर निगम - चिक्कमंगलुरु
8. कोलार नगर निगम - कोलार
9. बोगडी नगर पंचायत - मैसूरु
10. अनवट्टी नगर पंचायत - शिवमोग्गा

इस पायलट चरण के परिणामों और अनुभवों के आधार पर, सरकार द्वारा पूरे भारत में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे।

******